उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-33/2019-सा-3-843/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0

लखनऊ:दिनाँक: 21 नवम्बर, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय:- दिनाँक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उ0प्र0 के पत्र संख्या-Book(C)/Pension Apportionment/515 दिनांक 02-04-2019 के क्रम में, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड के मध्य आंकडों के मिलान तथा इंगित अवधि में दोनों राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप दोनों राज्यों के मध्य परस्पर देयता के संबंध में सहमति की शर्त के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2331.8950 करोड़ (रूपये दो हजार तीन सौ इकत्तीस करोड़ नवासी लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को किया जा चुका है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उक्त मद हेतु रू0 3000.00 करोड़ की व्यवस्था करायी गयी है जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2019 तक रू0 1400.00 करोड़ का भुगतान तदर्थ रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किया जा चुका है।

3- उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 1600.00 करोड़ में से आठवीं किश्त के रूप में तदर्थ रूप से रू0 200.00 करोड (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अधीन लेखाशीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0 प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के नामे डाला जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 33 /2019-सा-3-843(1)/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।